सत्यमेव जयते

State Environment Impact Assessment Authority, M.P.

(Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India)

Environmental Planning & Coordination Organization

Paryavaran Parisar, E-5, Arera Colony
Bhopal - 462016
visit us http://www.mpseiaa.nic.in
Email : mpseiaa@gmail.com
Tel.: 0755 - 2466970, 2466859
Fax : 0755 - 2462136

प्रति,

No.: 1929 /SEIAA/22
Date: 28/10/22

श्री राघवेन्द्र सिंह,
आत्मज श्री मेघराज सिंह,
निवासी सी–28, उर्मिला मार्ग, हनुमान नगर, वैशाली नगर,
जयपुर (राजस्थान) –302021

विषयः– **प्रकरण कमांक 9314/2022** परियोजना प्रस्तावक श्री राघवेन्द्र सिंह आत्मज श्री मेघराज सिंह, निवासी सी–28, उर्मिला मार्ग, हनुमान नगर, वैशाली नगर, जयपुर (राजस्थान) –302021 द्वारा रेत खदान, उत्पादन क्षमता 34,560 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.0 हेक्टेयर, खसरा 1331 ग्राम खेरियासिंध, तहसील मेहगॉव, जिला भिण्ड (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन। **Prescribing of TOR**

संदर्भः–752वी SEIAA बैठक दिनांक 15.10.2022 एवं 596वी SEAC समिति बैठक दिनांक 23.09.2022

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 596वी बैठक दिनांक 23.09.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ अतिरिक्त ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

(i) परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहुंच मार्ग के साथ–साथ लीज क्षेत्र की परिधि में वन विभाग के परामर्श से वृक्षारोपण की योजना तैयार की जाएगी और सभी विवरणों के साथ वास्तविक स्थल की तस्वीरों को ई.आई.ए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये ।

(iii) मैन्युअल खनन से संबंधित पाउडर/डस्ट फैक्टर के मूल्यांकन कर दस्तावेजों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। यह सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर (एसपीएम) के अनुमान को सुनिश्चित करेगा एवं खदान श्रमिकों पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव को समझने के साथ ही कार्यस्थल जनित रोगों की संभावना का मूल्यांकन करने में सहायक होगा।

(iv) खनन गतिविधियों से ग्लोबल वार्मिंग पोटेंसिएल और कार्बन फुट प्रिंट और इसे कम करने के उपायों का अध्ययन किया जाना चाहिए और प्रस्तावित ऊर्जा दक्षता उपायों के साथ ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये ।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जहां तक संभव हो गैर परंपरागत ऊर्जा स्त्रोतों के उपयोग हेतु योजना तैयार कर इसे रिपोर्ट में सम्मलित की जाये ।

(vi) पर्यावरण, वन एव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 18–02–2022 के प्रारूप अधिसूचना अनुसार ई.आई.ए. में जनरेटर सेटों के उत्सर्जन मानकों के अनुरूप तौर–तरीकों पर विचार किया जाना चाहिए।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अध्ययन में वायु गुणवत्ता मॉडलिंग को शामिल करना सुनिश्चित करेगा

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से एवं उनके द्वारा सुझाये गये स्थान पर खदानों से होने वाले प्रदूषण हेतु निरंतर मॉनिटरिंग इक्यूपमेन्ट लगाकर उसका डिस्प्ले किया जायें एवं अन्य ऐसे पर्यावरणीय बिन्दुओं जो कि समान रूप से सभी पर लागू है की सामूहिक रूप से कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा ईआईए में इसका विस्तृत रूप से विवरण दिया जायें।

(ix) पर्यावरण, वन एव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में रेत खदानों के कलस्टर Situation से संबंधित दिशा निर्देश प्रावधानित किये गये है जिसमें कलस्टर की दूरी, उसका एरिया, तथा अन्य प्रावधानों का भी उल्लेख किया गया है जिसका परिपालन आवश्यक है। अतः ईआईए में उक्त प्रावधानों का समुचित अध्ययन कर और यदि आवश्यक हो तो प्रावधानासुर आवश्यक संशोधन कर ईआईए में इसका विस्तृत उल्लेख किया जाये। SEIAA द्वारा पर्यावरण स्वीकृति देने पर विचार करते समय उक्त गाइडलाईन के प्रावधानों के अनुसार निर्णय लिया जायेगा।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निविदा में निविदत्त मात्रा से अधिक उत्पादन मात्रा का उत्खनन नहीं किया जायेगा इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा का विवरण ईआईए रिपोर्ट में सम्मलित किया जाये।

(xi) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन के O.M. No. Z&11013/57/2014&I.A. II (M) दिनांक 29/10/14 के अनुसार अध्यनन कर विवरण ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

(xii) खनिज परिवहन के दौरान परिवहन मार्ग पर रिफलेक्टरो की स्थापना, स्पीड ब्रेकर एवं रोड जंक्शन के विकास के लिए उपयुक्त बजट पर्यावरण प्रब धन योजना में शामिल कर ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।

(xiii) परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ जियोटेग फोटोग्राफ मय संबंधित खनिज अधिकारी का प्रमाण–पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि आवंटित खनन् क्षेत्र में खनन् हेतु स्वीकृत मात्रा में रेत उपलब्ध है ।

(xiv) यदि लीज एरिया के अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम में कोई रोड़, ब्रिज/या अन्य कोई सिविल निमाण जैसे : स्टापडेम अथवा कॉजवे इत्यादि लीज मे या लीज के आसपास स्थित हो तो वहॉ मॉनिटरिंग एवं इंफोर्समेंट गाइडलाईन, 2020 (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित) के अंतर्गत सुरक्षित दूरी छोड़े एवं इसका सम्पूर्ण विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

(xv) यदि नदी का प्रवाह आवंटित लीज क्षेत्र से हो रहा हो तो नदी के पानी के क्षेत्र को गैर खनन् क्षेत्र के रूप मे छोड़कर एवं यदि कोई सहायक नदी/नाला आवंटित लीज क्षेत्र में मिल रहा हो तो सेंड माईनिंग गाइडलाइन, 2016 एवं 2020 के दिशा–निर्देशों के अनुसार उसे गैर खनन् के रूप में छोड़ते हुए संशोधित नक्शा (सरफेस मेप) ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

(xvi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वचन–पत्र कि यदि खनन् क्षेत्र के किनारों पर हरित क्षेत्र अस्तित्व में हो तो ऐसे क्षेत्रों को गैर खनन् क्षेत्र के रूप में सुरक्षित रखा जावेगा तथा संशोधित नक्शा (सरफेस मेप) योजना ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाये।

(xvii) रेत परिवहन मार्ग को गूगन नक्शें में अंकित कर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

(xviii) आवंटित खनन् क्षेत्र के किनारों पर भू–क्षरण रोकने हेतु समुचित वृक्षारोपण योजना एवं आसपास स्थित शासकीय भूमि पर ड्रोन के माध्यम से सीड वॉल तकनीक पर आधारित वृक्षारोपण योजना की संभावनाओं का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

(xix) आवंटित खनन् क्षेत्र में यदि एक्वेटिक फोना ब्रीडिंग क्षेत्र हो तो उसकी जानकारी ई.आई.ए. रिपोर्ट में मय संरक्षण योजना के प्रस्तुत करें।

(xx) आवंटित खनन् क्षेत्र के आसपास शासकीय भूमि पर रेनवॉटर हार्वेस्टिंग की संरचनाओं के निर्माण की संभावनाओं का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

(xxi) आवंटित खनन् क्षेत्र के आसपास की भूमि पर एग्रोफॉरेस्ट्री की संभावनाओं का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

(xxii) चूँकि खदान नदी के क्षेत्र में स्थित है, अतः सम्पूर्ण खदान क्षेत्र का डी.जी.पी.एस. सर्वे कर उस पर संबंधित खनिज अधिकारी प्रमाणीकरण प्राप्त कर, खदान के सभी डी.जी.पी.एस. को–आर्डिनेट ईआई.ए. रिपोर्ट के साथ संलग्न कर प्रस्तुत किया जाये, जिससे गूगल इमेज में खदान का सम्पूर्ण क्षेत्र दर्शित हो सके। यदि डी.जी.पी.एस. सर्वे के पश्चात् प्राप्त को–आर्डिनेट तथा वर्तमान में अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अंकित को–आर्डिनेट में कोई सुधार वांछित हो तो उसे संबंधित जिला खनिज अधिकारी के संज्ञान में लाकर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट मे अंकित कर उस पर अनुमोदन भी प्राप्त किया जाये।

Documents to be submitted:

Environmental Consultant / PP

I. A certificate from the Consultant shall be submitted that they have been accredited by MoEF (GoI), as per OM.

II. The Project Proponent shall submit an undertaking as part of EIA report regarding data authenticity and owning the contents of EIA report as per OM dated 05/10/2011.

III. Final EIA report including public hearing and EMP various aspects should be submitted to the SEIAA.

IV. All information with supporting documents as prescribed by SEIAA in the O.M. No. 966 dated 27/01/2012 has to be furnished with the EIA report. Failing this the EIA report shall be returned to the PP.

V. Necessary clearance from the Competent Authority for drawl of requisite quantity of water for the project should be provided.

VI. PP should provide latest notarized copy of Khasra Panchsala (P-II) indicating ownership. If the ownership is different than a notarized copy of the agreement should be submitted. Besides, notarized copy of the lease agreement should also be submitted clearly indicating sanction period & ownership.

VII. Notarized copy of the approved mining plan.

VIII. Location of National Parks, Sanctuaries, biosphere Reserves, Wildlife corridors, Tiger reserves (existing as well as proposed), if any, within 10 km of the mine lease should be clearly indicated. A location map duly authenticated by Chief Wild life Warden and recommendation/ comments of Chief Wildlife Warden of concerned district should also be provided in this regard.

IX. A letter from District Collector Office / Executive Engineer PWD indicating distance of mine area from inter-state boundary and critically polluted/ sensitive areas notified by CPCB/MoEF.

X. DFO letter indicating the distances of nearest forest boundary from the boundary of the proposed site.

* *In case the distance of nearest forest boundary is up to 250 meters or less, then NOC as per orders issued by forest department from time to time is required.*

XI. NOC from Gram Sabha if located in scheduled notified area.

XII. Other mandatory permissions and clearances from various authorities.

XIII. All TOR prescribed in the standard TOR published by MoEF&CC shall be applicable.

Other points to be addressed in the EIA/EMP report:

➢ Recent land use features in the region.

➢ Map Depictions: Coloured maps depicting land-use of the region showing sensitive / fragile features and detailed lay-out of the site clearly showing green-belt (existing & planned).

➢ Location is also to be shown in Tehsil map procured from revenue department, showing exact distances of highway, railway & habitat and all other sensitive area from the site.

➢ Details of land to be provided in following format:

S.No.	Tehsil	Village	Khasra No.	Area	Ownership	Land use

➢ Compliance of the conditions laid in the consent / EC should be supported with photograph of the site clearly showing plantation etc (if any).

➢ Summary of EIA / EMP has to be provided separately along with the EMP detailing impacts, impact zone and mitigations has to be furnished in the following format:

AIR Environment

SN	Expected Impact	Impact zones	Management Plan

WATER Environment

SN	Expected Impact	Impact zones	Management Plan

LAND Environment

SN	Expected Impact	Impact zones	Management Plan

NOISE Environment

SN	Expected Impact	Impact zones	Management Plan

Details of Public Hearing Proceedings

SN	Issues raised (details thereby)	Response of Proponent	Comments

➢ To-the-scale map showing locations of all the mines in 500m radius around the site have to be furnished.

- Source of water for the project with permission / commitment from the competent authority to be submitted.
- Water consumption in the project has to be evaluated including all the usages.

General Conditions

1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.
2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
8. All documents should be properly indexed, page numbered.
9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the

capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.

20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.
21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analysed.
26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in- situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
29. LPG gas shall be provided for camping labour under "UjjwalaYojna .
30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The under taking interalia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
33. **Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:**

- Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.
- Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
- No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "UjjwalaYojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.
- PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.

34. **Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for :**

    - Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.
    - Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned/Gram Panchayat/ Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
    - Commitment that high density plantation (preferably using "Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.
    - Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area and handed over to Gram Panchayat after lease period.
    - PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
    - Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.
    - Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP

35. खदान क्षेत्र मे किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देशः–

i. स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए।

ii. विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रूचि रखने वाले स्थानीय जानकारो से राय ली जाने की सलाह है।

iii. पौधो की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख–रेख, मृदा नमीं को बनाये रखने हेतु जल–संरचनाओं का निर्माण, निदाई –गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए।

iv. पौधों की ऊँचाई / गोलाई –

v. भू–क्षरण स्थल पाये जाने पर भू–संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।

vi. **रोपित पौधो का मापदंड एवं अन्य कार्यः–**

सं	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1	बैरियर जोन / नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से.मी.
2	रोड़ साईड / स्कूल / ऑगनवाडी	03.5 फिट	05 से.मी.
3	पौधों के चारों ओर निदाई–गुड़ाई, थाला (1.5 मी. गोलाई में) बनाना तीन वर्षो तक ।	.	.
4	आवश्यक्तानुसार सिंचाई ।	.	.

vii. **बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख–रेखः–**

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई / जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुँआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियॉ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई–गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षो तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना।
- सीड–बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA , following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.

36. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
37. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
38. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.

39. The consent of Gram Sabha of the villages in the area where project is proposed shall be obtained.

Validity:–

- The TORs prescribed for the project will be valid for a period of Three years for submission of EIA and EMP report accordingly, the TORs will lapse after 14.10.2025.
- This period of validity could be extended by the Regulatory Authority concerned by a maximum period of one year provided an application is made by the applicant to the Regulatory Authority before the expiry of validity period, together with updated Form-I based on proper justification and also recommendation SEIAA/SEAC.

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

Endt No. 1930 / SEIAA/22 Dated: 28/10/22

Copy to:-

1. सदस्य सचिव, SEAC, अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल – 462016।
2. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल – 462016।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, भूतल सतपुड़ा भवन, भोपाल (म.प्र.)
4. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड़ नं. 03, व शंकर नगर, भोपाल – 462016।
5. संबंधित फाईल।

(आलोक नायक)
प्रभारी अधिकारी